



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1931 (श0)
(सं0 पटना 625) पटना, शुक्रवार, 18 दिसम्बर 2009

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण
(पथ निर्माण विभाग)
बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम्
अधिकरण विनियमन, 2009

अधिसूचना
24 नवम्बर 2009

सं0 प्र0-6/नियम-03/2008/13577 (एस)—बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा-10 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, बिहार लोक संविदा विवाद माध्यस्थम अधिकरण राज्य सरकार की मंजूरी के साथ निम्नलिखित विनियमन बनाती है, यथा:—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :—(i) ये विनियमन बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम अधिकरण विनियमन 2009 कहे जायेंगे।

(ii) ये विनियमन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे एवं प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ :—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से परे अपेक्षित नहीं हो :—

- (a) “अधिनियम” का अर्थ है बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 2008 ;
- (b) “निर्देश” का अर्थ है बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत निर्देश ;
- (c) “निबंधक” का अर्थ है बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम अधिकरण का निबंधक जिसमें संयुक्त निबंधक तथा उप-निबंधक सम्मिलित रहेंगे ;
- (d) शब्द और अभिव्यक्ति जो इन विनियमनों में पारिभाषित नहीं हुये हैं ; किन्तु बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 2008 (इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में प्रयुक्त) में पारिभाषित किए गये हैं अथवा उसके अधधीन गठित नियमावली में जो अर्थ प्रयुक्त है वही अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप समझा जाएगा।

3. अधिकरण को निर्देश—विहित प्रपत्र में दिए गए निर्देश (माध्यस्थम के लिए याचिका) को निबंधक के सामने अथवा निबंधक के द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को याचिकाकर्ता या उनके बदले में अर्जीदार के द्वारा अथवा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता अथवा किसी वकील के द्वारा अधिकरण के कार्य समय के दौरान उपस्थापित किया जा सकेगा।

4. निर्देश की प्राप्ति पर प्रक्रिया—अधिकरण के कार्यालय में निर्देश प्राप्त होते ही निर्देश के साथ शपथ—पत्र तथा दस्तावेजों को जिम्मेदार पदधारी अथवा अधिकरण के ऐसे कर्मचारी जो इस निमित्त अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के तहत अधिकृत हो, के द्वारा संवीक्षा की जाएगी।

5. निर्देश में यदि किसी प्रकार का दोष या कमी प्रकट होती है तो इसे निबंधक अथवा निबंधक के द्वारा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी को प्रतिवेदित किया जाएगा जो अर्जीदार को एक निश्चित तय समय के अंदर इसे सुलझाने का दिशा—निर्देश देंगे।

6. दोष अथवा कमी को दूर कर लेने के बाद उक्त निर्देश को पंजीकृत, क्रमांकित करते हुए अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. (i) विवाद की प्रकृति अन्तर्ग्रस्त राशि एवं अन्य संगत प्रभाव डालने वाली बातों के मद्देनजर, यदि कोई हो, अध्यक्ष द्वारा किसी न्यायपीठ को नियत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक न्यायापीठ में अध्यक्ष एवं एक सदस्य या दो सदस्य होगा, जिसमें दो सदस्यीय पीठ के लिए एक सदस्य तकनीकी पृष्ठभूमि से तथा एक सदस्य प्रशासनिक/न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे।

8. न्यायपीठ जिसे कि निर्देश सौंपा गया हो वह हाजिरी के दिन को विनिर्दिष्ट करते हुए विरोधी पक्षकार (प्रत्यर्थी) को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

9. अर्जी (निर्देश) की एक कॉपी के साथ सूचना विरोधी पक्षकार (प्रत्यर्थी) को उनके पते पर निबंधित पावती के द्वारा उस पते पर भेजी जाएगी जो अर्जीदार ने दर्शायी है अथवा बाद में अर्जीदार द्वारा प्राप्त पता या प्रतिपक्षी के अभिकर्ता के द्वारा अंकित पता पर प्रदत्त हो।

10. सूचना में विनिर्दिष्ट हाजिरी की तारीख अथवा उसके पहले विरोधी पक्षकार लिखित जवाब स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अथवा अधिकृत अभिकर्ता के द्वारा बनाया गया जवाब एक शपथ—पत्र के साथ प्रकथन सत्यापित करते हुए दाखिल कर सकते हैं।

11. सिविल प्रक्रिया की संहिता के आदेश के नियम 1 से 6 के अनुरूप अधिकरण अथवा इसके न्यायपीठों के समक्ष चलेगी।

12. अर्जीदार अपने निर्देश के समर्थन में सभी दस्तावेज और सबूत जिसके आधार पर उसका दावा स्थापित होता है दाखिल करेगा ; विपक्षी भी उसी प्रकार अपने वचाव का सभी दस्तावेज, जिस पर वह निर्भर हो, अपने बचाव में पेश करेगा।

13. यदि डाक सामग्री में अन्तर्विष्ट नोटिस अथवा समन इस पृष्ठांकन के साथ जो डाककर्मी द्वारा किया गया तात्पर्यित हो, लौटाया जाय कि प्रेषिती अथवा उसके अभिकर्ता ने यथास्थिति नोटिस अथवा समन से अन्तर्विष्ट डाक सामग्री देने वक्त लेने से इनकार कर दिया था तो इसे निर्गत करनेवाला न्यायाधिकरण अथवा न्यायपीठ यह घोषणा करेगा कि नोटिस अथवा समन सम्यक् रूप से तामील करा दिया गया है ;

परन्तु इस तथ्य के होते हुए भी कि नियत तारीख के पूर्व डाक पावती प्राप्त नहीं हुई है, उपर्युक्त निर्दिष्ट घोषणा की जा सकेगी।

14. प्रतिस्थापित तामील—जहाँ न्यायाधिकरण अथवा न्यायपीठ का समाधान हो कि यह विश्वास करने का कारण है कि प्रेषिती तामील होने से बच रहा है अथवा किसी अन्य कारणों से नोटिस अथवा सम्मन डाक द्वारा तामील नहीं कराया जा सकता हैं तो न्यायाधिकरण अथवा न्यायपीठ यह आदेश देगा कि नोटिस अथवा सम्मन को उस क्षेत्र में, जहाँ प्रेषिती जानकारी के अनुसार वह हाल तक रहा हो अथवा कार्य किया हो अथवा कारोबार किया हो, परिचालित होने वाले दैनिक समाचार—पत्र में विज्ञापन देकर अथवा ऐसी रीति से जो वह उचित समझें तामील करायेगा।

15. दस्तावेजों की खोज, निरीक्षण तथा ग्रहण—सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XI तथा XII के अधीन नियमावली न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों पर लागू होगी।

16. विवादक—विवादकों का स्थिर किया जाना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु न्यायाधिकरण या न्यायपीठ किसी विशिष्ट मामले में उसके औचित्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकेगा।

17. साक्षियों को सम्मन एवं उनकी उपस्थिति—न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVI के नियम 1 से 21 तथा आदेश XVII के नियम 1 से 7 लागू होंगे।

18. सम्मन की तामील—प्रत्येक सम्मन जो तामील हेतु किसी पक्षकार को सम्मन के रूप में परिदत्त न हो, की तामील लगभग उसी प्रकार से की जा सकेगी जैसा कि प्रतिवादी को सम्मन तामील कराई जाती है और तामील के साक्ष्य से संबंधित समान नियम प्रयोज्य होंगे।

19. तामील हेतु पक्षकार को प्रदत्त सम्मन—किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करने हेतु किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायाधिकरण ऐसे पक्षकार को ऐसे व्यक्ति पर ऐसे सम्मन की तामील करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसे मामले में तामील हेतु ऐसे पक्षकार को सम्मन हस्तगत करा सकेगा। इस विनियमन के अधीन तामील सम्मन तामील पदाधिकारी द्वारा यथा तामील माने जायेंगे। जहाँ इस विनियमन के अधीन किसी पक्षकार द्वारा समन तामील कराया जाता हो तो उस पक्षकार से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि समन की तामील हेतु अन्यथा प्रभार्य शुल्क अदा करें।

20. सम्मन निकलवाए बिना साक्षियों का पेश किया जाना—माध्यस्थम् का कोई पक्षकार न्यायाधिकरण की अनुमति से सम्मन निकलवाए बिना किसी साक्षी को साक्ष्य देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए ला सकेगा।

21. पक्षकारों की हाजिरी तथा गैर-हाजिरी का परिणाम—सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 1 से 14 के उपबंध न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

22. स्थगन—यदि कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पर्याप्त कारण दर्शाया जाय तो न्यायाधिकरण अथवा मामला (केस) की सुनवाई करनेवाला न्यायपीठ अधिनियम की धारा-9(4) के अध्यक्षीन पक्षकारों अथवा उनमें से किसी को समय दे सकेगा, समय-समय पर मामला की सुनवाई स्थगित कर सकेगा।

ऐसे प्रत्येक मामला में न्यायाधिकरण मामला की आगे की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा तथा स्थगन के कारण होनेवाले व्यय के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

23. मामला की सुनवाई—प्रतिवादी अथवा उनकी ओर से लिखित उत्तर दिए जाने के पश्चात् विवाद के प्रश्न के निपटान तथा उससे संबंधित मामले के समर्थन में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले साक्ष्य हेतु एक तारीख नियत की जाएगी।

24. अंतिम सुनवाई—अवधार्य प्रश्न तथा साक्ष्य के निपटान होने पर मामला की अंतिम सुनवाई की जाएगी।

25. अन्य साक्षी के समक्ष पक्षकार का हाजिर होना—जहाँ कोई पक्षकार स्वतः साक्षी के रूप में हाजिर होना चाहता हो तो वह अपनी ओर से किसी अन्य साक्षी के परीक्षण के पूर्व उपस्थित होकर साक्ष्य दे सकता है — यदि उसे वाद में साक्षी के रूप में हाजिर होने की अनुमति न दी गई हो।

26. साक्ष्य का ज्ञापन—किसी साक्षी के साक्ष्य को विस्तार से लिखना अथवा लिखवाना अथवा अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा लेकिन यथास्थिति सदस्यों में से कोई एक अथवा एकमात्र सदस्य जो साक्षी की परीक्षा के समय मामला की सुनवाई कर रहा हो, अभिसाक्ष्य लेखक को सार का ज्ञापन लिखवाएगा जो अभिसाक्ष्य साक्षियों ने दिया हो तथा ऐसा ज्ञापन न्यायपीठ के सदस्यों अथवा एकमात्र सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और यह अभिलेख का हिस्सा होगा ; परन्तु साक्ष्य को अभिलिखित करने के बदले न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य अथवा तथ्यों को प्रमाणित करनेवाला शपथ-पत्र लिया जा सकेगा तथा अन्य पक्षकार को प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की अनुमति दी जा सकेगी।

27. साक्ष्य का अनुक्रम—मामला की सुनवाई करनेवाला न्यायपीठ यह निर्णय लेगा कि विनियम 25 के अध्यक्षीन निपटारा करने की तारीख को साक्ष्य किस अनुक्रम में रखा जाय।

परन्तु, मामला की सुनवाई करनेवाला न्यायपीठ अथवा न्यायाधिकरण साक्ष्य के अनुक्रम को परिवर्तित कर सकेगा जब भी ऐसा करना आवश्यक हो तथा अतिरिक्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने की तथा इस निमित्त कारणों को अभिलिखित कर नये साक्षी की परीक्षा करने की अनुमति दे सकेगा।

28. शपथ-पत्र द्वारा किसी बात को प्रमाणित करने का आदेश देने की शक्ति—मामला की सुनवाई करनेवाला न्यायाधिकरण अथवा न्यायपीठ किसी भी समय आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट तथ्य अथवा तथ्यों को शपथ-पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाय अथवा सुनवाई के समय किसी साक्षी का शपथ-पत्र ऐसी शर्तों पर साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाय जो न्यायाधिकरण अथवा न्यायपीठ उचित समझें।

29. प्रतिपरीक्षा के लिए अभिसाक्षी को हाजिर होने का आदेश देने की शक्ति—पक्षकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य दिया जा सकेगा। लेकिन अन्य पक्षकार के अनुरोध पर न्यायालय अभिसाक्षी को प्रतिपरीक्षा हेतु हाजिर होने का आदेश दे सकेगा अथवा अभिसाक्षी की प्रतिपरीक्षा के बदले प्रतिशपथ दायर करने का आदेश दे सकेगा।

30. निरीक्षण करने की शक्ति—कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में न्यायाधिकरण अथवा न्यायपीठ विवाद से संबंधित किसी सम्पत्ति अथवा चीज का निरीक्षण कर सकेगा। परन्तु निरीक्षण किए जाने पर वह एक ज्ञापन तैयार करेगा जो मामला के अभिलेख के भाग के रूप में होगा।

31. अधिनर्णय—मामला के सुने जाने के पश्चात् यथास्थिति न्यायाधिकरण अथवा न्यायपीठ तुरंत अथवा उसके पश्चात् भविष्य में यथासाध्य शीघ्रता से अधिनर्णय की घोषणा करेगा जिसके लिए पक्षकारों अथवा उनके अधिवक्ताओं को सम्यक् नोटिस दी जाएगी। मामला की सुनवाई करनेवाले सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा अधिनर्णय पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

31. (A) व्यय—न्यायाधिकरण अथवा न्यायपीठ ऐसे वाद विचारण के दौरान किसी प्रकार के व्यय का अधिभारण किसी पक्षकार पर कर सकेगा, जैसा वह उचित समझें।

32. कमीशन, कमीशन का निर्गमन—गवाहों का परीक्षण; लेखा परीक्षण ; अथवा स्थानीय निरीक्षण या परीक्षण या किसी अन्य प्रयोजन जो किसी मामले के निष्पादन हेतु आवश्यक हो ; के लिए खण्डपीठ ऐसे शर्तों पर कमीशन निर्गत कर सकती है, जो वे उचित समझें।

33. साक्ष्य के लिए प्रतिवेदन एवं कार्यवाही—कमीशन की कार्यवाही एवं प्रतिवेदन (यदि कोई हो) उस मामले में साक्ष्य होंगे। किन्तु जहाँ न्यायाधिकरण या खंडपीठ उनसे किसी कारणवश असंतुष्ट हो तो ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझें।

34. किंचित खास परिस्थितियों में कार्यवाही को जारी रखा जाना—(i) अध्यक्ष या किसी सदस्य की अनुपस्थिति अथवा अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद की रिक्ति के वावजूद न्यायाधिकरण कार्यवाही को जारी रख सकता है,

(ii) किसी कार्यवाही के दौरान न्यायाधिकरण के गठन में रिक्ति के भरे जाने अथवा किसी कारणवश परिवर्तन हो तो, ऐसी कार्यवाही को पुनः नये सिरे से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी और उक्त कार्यवाही उसी स्तर से निरंतर चल सकेगी जिस स्तर पर ऐसा परिवर्तन हुआ तथा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत वैसे साक्ष्य, शपथ-पत्र और अन्य तात्विक सामग्रियों के आधार पर, जो ऐसे गठन के पूर्व प्रस्तुत हुये हों, के आधार पर न्यायाधिकरण कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी।

35. अभिवचन पर संघात—अधिकरण अपने समक्ष दायर किये गये किसी अभिवचन में ऐसा संशोधन कर सकता है अथवा आदेश दे सकता है कि ऐसे अंश को विलोपित कर दिया जाय जो :

- (क) अनावश्यक, कष्टप्रद, कलंकित या तुच्छ हो या
- (ख) सन्दर्भ के निष्पक्ष परीक्षण के पूर्वाग्रह, उलझन या विलम्ब की ओर प्रवृत्त हो सकता है या
- (ग) कि न्यायाधिकरण की प्रक्रिया का अन्यथा दुरुपयोग हो।

36. याचिका खारिज करना—निम्नलिखित मामलों में याचिका खारिज की जायेगी :—

- (क) जहाँ कार्रवाई के कारण को प्रकट नहीं किया गया हो,
- (ख) जहाँ राहत का दावा वास्तविक से कम निर्धारित किया गया हो और न्यायाधिकरण के द्वारा निश्चित समय के अन्दर दावा का उचित मूल्यांकन न किया जाता हो,
- (ग) जहाँ राहत का दावा उचित रूप से मूल्यांकित किया जाता हो, किन्तु न्यायाधिकरण के द्वारा न्यायालय शुल्क के भुगतान के संदर्भ में नियम समय के अन्दर आवश्यकतावश अपर्याप्त रूप से मुहरित करने में असफल हो।
- (घ) जहाँ याचिका में विधि द्वारा वर्जित प्रसंग प्रतीत हो।

37. प्रसंग को नामंजूर की प्रक्रिया—याचिका रद्द किये जाने की स्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा याचिका रद्द किये जाने के कारण देते हुए लिखित आदेश पारित करेगा।

38. सन्दर्भों की वापसी एवं समायोजन—(i) संदर्भ के संस्थापन के पश्चात् किसी समय आवेदनकर्ता सभी या किसी प्रतिवादियों के विरुद्ध अपना संदर्भ या अपने दावा का कोई भाग परित्याग कर सकता है।

(ii) जहाँ न्यायाधिकरण संतुष्ट हो :—

- (क) कि संदर्भ किसी औपचारिक त्रुटि के कारण असफल होगा।
- (ख) कि आवेदनकर्ता को एक नया संदर्भ दाखिल करने का पर्याप्त कारण है तो वह आवेदनकर्ता को संदर्भ अथवा उसका कोई अंश जो वह उचित समझे को वापस लेने तथा नये संदर्भ दायर करने की अनुमति दे सकेगा।

(iii) जहाँ आवेदनकर्ता :—

- (क) उप-नियम (1) के अधीन किसी संदर्भ या दावा का भाग का परित्याग करता है अथवा
- (ख) बिना अनुमति के संदर्भ या उसका अंश वापस लेता है तो वह ऐसे व्ययों के उत्तरदायी होंगे जैसा का न्यायाधिकरण अधिनिर्णय करे और उक्त संदर्भ के विषय वस्तु से संबंधित किसी नये संदर्भ दायर नहीं कर सकेगा।

39. संदर्भ का सुलह—जहाँ न्यायाधिकरण संतुष्ट हो कि प्रसंग का समायोजन पक्षकार के द्वारा किसी कानूनी करार या लिखित एवं हस्ताक्षरित सुलह या जहाँ प्रत्यर्थी आवेदनकर्ता के प्रसंग को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से तुष्ट करता हो तो न्यायाधिकरण ऐसे सुलह को अभिलेखित कर विधि सम्मत निर्णय पारित करेगा।

40. निबंधक की शक्तियाँ एवं कार्य—(i) न्यायाधिकरण के अभिलेखों की अभिरक्षा का जिम्मा निबंधक को होगा जो ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे जैसा उन्हें इन नियमनों के तहत या अध्यक्ष के विशेष आदेश के द्वारा हस्तांतरित किया गया हो।

(ii) निबंधक, अध्यक्ष की सहमति से किसी कार्य या अपेक्षित शक्ति का निष्पादन के लिए संयुक्त निबंधक, उपनिबंधक/प्रशाखा पदाधिकारी का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(iii) निबंधक की अनुपस्थिति में संयुक्त निबंधक, उपनिबंधक/प्रशाखा पदाधिकारी निबंधक के समस्त कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

(iv) कार्यालय के मुहर निबंधक के अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(v) अध्यक्ष के सामान्य या विशेष निर्देश के अध्याधीन न्यायाधिकरण का मुहर निबंधक या संयुक्त निबंधक/उपनिबंधक/प्रशाखा पदाधिकारी के लिखित अधिकार के अधीन किसी आदेश अथवा समन अथवा अन्य प्रक्रिया के लिए संबद्ध नहीं किया जा सकेगा।

40 (A) निबंधक के अतिरिक्त शक्तियाँ एवं कर्तव्य—इन नियमनों में प्रदत्त शक्तियाँ के अतिरिक्त, निबंधक को अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अध्याधीन निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे।

- (i) निबंधित करने के पूर्व सभी आवेदनों/अभ्यावेदनों की संवीक्षा से उठे सभी प्रश्नों पर निर्णय करना।
- (ii) न्यायाधिकरण मामले की आवश्यक सुनवाई से संबंध किसी आवेदन/अभ्यावेदन को विधि के अनुरूप संशोधित करने का आदेश देना।
- (iii) न्यायाधिकरण अभिलेखों का निरीक्षण की अनुमति देने।
- (iv) किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकार की रक्षा से अभिलेखों का अधिग्रहण।
- (v) पार्टी के द्वारा कागजातों की वापसी एवं आवेदनों को प्राप्त कर निपटारा करना।

41. खण्डपीठों का संविधान—अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसरण में समय-समय पर ऐसा आदेश निर्गत कर अध्यक्ष न्यायाधिकरण के मामलों और विषयों के लिए खंडपीठों के गठन को सुविधाजनक संव्यवहार विनियमित करेगा।

42. मुहर—न्यायाधिकरण अपने लिए मुहर का प्रयोग करेगा।

43. कार्य अवधि—न्यायाधिकरण का कार्यालय एवं न्यायालय अधिकृत अवकाशों के अतिरिक्त उनके समक्ष करोबार के संव्यवहार को निपटाने के लिए प्रतिदिन खुले रहेंगे। न्यायाधिकरण या खंडपीठों की कार्यवाही अपराह्न 10 बजे से पूर्वाह्न 5 बजे के बीच चलेगी, साथ ही अपराह्न 1:30 से अपराह्न 2.15 के बीच मध्यावकाश रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष के द्वारा समय में उपयुक्त परिवर्तन किया जा सकेगा। कार्यालय अवधि राज्य सरकार के कार्यालयों के अनुरूप होगा।

44. न्यायाधिकरण के कतिपय अन्य मामलों में प्रक्रिया—सूचना एवं प्रतिलिपियों की प्राप्ति, अभिलेखों के संरक्षण, भंजन और अभिरक्षा, अभिप्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करना, लेखा से संबंधित कार्यवाही और उसका देखभाल, न्यायालय शुल्क की पर्चियों का निर्सन, विधि व्यवसायिक लिपिक तथा पूर्व में अनिर्दिष्ट न्यायाधिकरण के व्यवहार एवं प्रक्रिया से संबंध अन्य कुछ मामलों का निबंधन न्यायाधिकरण के अधिनियम और नियमावली के सुसंगत व्यवहार और स्वरूप में जैसा कि न्यायाधिकरण के प्रति लागू हो ; यह न्यायाधिकरण प्रक्रिया के मामले में पटना उच्च न्यायालय की नियमावली और परिपाटी का अनुकरण करेगा जबतक कि न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे मामलों पर अलग से कोई विनियमन बनाया जाय।

45. वादों की सूची—वादों के चरण, वादों की प्रकृति, वाद संख्या, पक्षकारों के नाम, पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अधिवक्ता और खंडपीठ, जिनके समक्ष सभी संबंधितों के सूचनार्थ वादों का पंजीयन किया गया है, को प्रतिदर्शित न्यायाधिकरण के कार्य व्यवहार को दर्शित करते हुए वाद सूची नियमित रूप से प्रकाशित की जायेगी।

न्यायमूर्ति सदानन्द मुखर्जी,

अध्यक्ष,

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद

माध्यस्थ न्यायाधिकरण।

BIHAR PUBLIC WORKS CONTRACTS DISPUTES ARBITRATION TRIBUNAL REGULATIONS, 2009.

The 24th November 2009

No. Sec.-6/Niyam-03/2008—13577 (S).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008, the Bihar Public contracts Disputes Arbitration Tribunal with the sanction of the State Government hereby makes the following regulations, namely :-

1. *Short title and Commencement*—(i) These regulations may be called the Bihar Public Works contracts Disputes Arbitration Tribunal Regulations, 2009.

(ii) The regulations shall be published in the Government Gazette and upon Publication shall become operative with immediate effect.

2. *Definitions*—In these Regulations, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008;

(b) "Reference" means reference under section 9 of the Bihar Public Works contracts Disputes Arbitration Tribunal Act.

(c) "Registrar" means the Registrar of the Bihar Public works contracts Disputes Arbitration Tribunal and includes Joint Registrar or Deputy Registrar.

(d) Words and Expressions used but not defined in these regulations but defined in Bihar Public Works contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008 (hereinafter

called the 'Act') and the rules framed there under, shall have the meaning assigned to them in the Act and the Rules.

3. *Reference to Tribunal*—Reference (petition for Arbitration) in the prescribed form shall be presented to the Registrar or an officer authorized by the Registrar in this behalf by the petitioner in person or by his duly authorized agent or advocate, during the working hours of the tribunal.

4. *Procedure on receipt of reference*— As soon as a reference is received in the office of the Tribunal, it along with the affidavit and documents shall be scrutinized by such responsible official or the staff of the Tribunal as the Chairman may, by general or special order, authorise in this behalf.

5. If any defect or deficiency is discovered in the reference, it shall be reported to the Registrar or an officer authorised by the Registrar in this behalf who shall direct the petitioner to remove it within a specified time to be fixed by him.

6. The reference, if found in order or after removal of the defect or deficiency, if any, shall be registered, numbered and placed before the Chairman.

7. (i) The Chairman shall, having regard to the nature of the dispute, the amount involved and other relevant factors, if any, assign it to a Bench for giving awards.

(ii) Each bench will consist of Chairman and one member or any 2 (Two) members provided that in latter case one member will be from technical background and one member from administrative/judicial background.

8. The Bench to which the reference is so assigned shall cause notice thereof to be issued to the opposite party (respondent) to show cause, specifying the date for appearance.

9. Notice to the opposite party (respondent) with a copy of the petition (reference) shall be sent by Registered A.D. in the address of the opposite party (respondent) furnished by the petitioner in petition for Reference or in any other or further address to be furnished by the petitioner or in the address of the agent of the opposite party (respondent).

10. The opposite party on or before the date specified in the notice for its appearance, may file a reply in writing signed by it or its authorized agent, along with an affidavit verifying the averment made in the reply.

11. The rules 1 to 6 of the Order III of the Code of Civil Procedure shall be applicable to the proceedings before the Tribunal or its Benches.

12. The reference shall be accompanied with all the documents on which the petitioner relies to establish his claim and the written reply of the opposite party shall likewise, be accompanied with all the documents which he intends to rely upon in deference or support of his case.

13. If the postal article containing the notice or the summons is received back with an endorsement purporting to have been made by a postal employee to the effect that the addressee or his agent had refused to take delivery of the postal article containing the notice or summons as the case may be when tendered to him, the Tribunal or the Bench issuing it shall declare that the notice or the summons has been duly served;

Provided that the declaration referred to above shall be made notwithstanding the fact that the postal acknowledgment has not been received back before the date fixed.

14. *Substituted service*—WHERE the Tribunal or the Bench is satisfied that there is reason to believe that the addressee is avoiding service or that for any other reason the notice or summons cannot be served by post, the Tribunal or the Bench shall order the notice or the summons to be served by an advertisement in a daily newspaper, circulating

in the locality in which the addressee is known to have last resided or worked or carried on business or in such manner as may be thought fit.

15. *Discovery, inspection and admission of documents*—The rules under order XI and XII of the civil procedure code shall be applicable to the cases before the tribunal.

16. *Issues*—It shall not be necessary to frame issues but the Tribunal or the Bench may do so far the sake of expediency in a particular case.

17. *Summoning and Attendance of witnesses*—The rules 1 to 21 of order XVI and rules 1 to 7 of Order XVIIA of the Civil Procedure Code will be applicable in the proceedings before the Tribunal.

18. *Summons how served*—Every summons not being a summons delivered to a party for service, shall be served, as nearly as may be in the same manner as a summons to a defendant and the same rules regarding proof of service shall apply.

19. *Summons given to a party for service*—The Tribunal may, on the application of any party for issuing a summons for the attendance of any person, allow such party to effect service of such summons on such person and shall, in such case, deliver the summons to such party for service.

The summons served under this regulation will be treated as served by a Serving officer. Where a summons is served by a party under this regulation, the party shall not be required to pay the fee otherwise chargeable for service of summons.

20. *Production of witnesses without summons*—Any party to the Arbitration may, without applying for summons, bring any witness to give evidence or to produce documents with the permission of the Tribunal.

21. *Appearance of parties and consequence of non-appearance*—Provisions of rules 1 to 14 of order IX of the civil Procedure Code, shall be applicable to the proceedings before the Tribunal .

22. *Adjournments*—The Tribunal or the Bench hearing the case may, if sufficient cause is shown at any stage of the proceedings, grant time to the parties or to any of them and may, from time to time, adjourn the hearing of the case, subject to Section 9(4) of the Act.

In every such case, the Tribunal shall fix a day for the further hearing of the case and may make such order as it thinks fit with respect to the costs occasioned by the adjournment.

23. *Hearing of the Case*—After the written reply is filed by or on behalf of the defendant, a date will be fixed for settlement of points in dispute and the evidence which the parties will adduce in support of their respective cases.

24. *Final hearing*—On settlement of points for determination and the evidence, the case shall be posted for final hearing.

25. *Party to appear before other witness*—Where a party himself wishes to appear as a witness he shall so, appear before any other witness on his behalf has been examined unless he is allowed to appear as his own witness at a later stage.

26. *Memorandum of evidence*—It shall not be necessary to take down or dictate or record the evidence of a witness at length, but one of the members or the sole member as the case may be, sitting to hear the case, while a witness is being examined, shall dictate to the deposition writer, a memorandum of the substance of what the witness deposed, and such memorandum shall be signed by the members of Bench or the sole member, hearing the case, and shall form part of the record.

Provided that in lieu of recording evidence, Affidavit to prove the fact or facts may be taken by the Tribunal and counter affidavit may be allowed to be filed by the other party.

27. *Sequence of evidence*—On the settling date, subject to regulation 25, the sequence in which the evidence may be taken shall be decided by the Bench hearing the Case;

Provided that the Tribunal or the Bench hearing the case, may change the sequence of evidence as and when it becomes necessary to do so and may also allow the producing of additional evidence and examination of a new witness for reasons to be recorded in this behalf.

28. *Power to order any point to be proved by affidavit*—The Tribunal or the Bench, hearing the case, may at any time, order that any particular fact or facts may be proved by affidavit or that the affidavit of any witness may be read as evidence at the hearing on such conditions as the Tribunal or the Bench thinks reasonable.

29. *Power to order attendance of deponent for cross-examination*—Upon an application made by a party, evidence may be given by affidavit, but the Court may at the instance of the other party, order the attendance of deponent for cross-examination or counter affidavit may be ordered to be filed in lieu of cross examination of the deponent.

30. *Power to inspect*—The Tribunal or the Bench may, at any stage of the proceedings, inspect any property or thing concerning the dispute but it on inspection shall make a memorandum which shall form part of the record of the case.

31. *Award*—The Tribunal or the Bench as the case may be, after the case has been heard shall pronounce its award, either at once or as soon thereafter as practicable on some future date, on which due notice shall be given to the parties or their pleaders. The award shall be signed by the member or members who hear the case.

31. A *Costs*—The Tribunal or the Bench may award such costs as deemed fit and proper.

32. *Commission, Issue of Commission*—The Tribunal or the Bench may, in any case, issue commission for examination of a witness or examination of accounts or local inspection or investigation or for any other purpose which may be considered necessary for the disposal of the case, on such terms and conditions as it thinks proper.

33. *Proceedings and Report to be evidence*—The proceedings and report (if any) of the Commission shall be evidence in the case but where the Tribunal or the Bench has reason to be dissatisfied with them, it may pass such orders as it thinks fit.

34. *Continuance of Proceeding in certain circumstances*—(i) In a case pending before the Tribunal, it may act notwithstanding the absence of the Chairman or any member or the existence of any vacancy in the office of the Chairman or any member;

(ii) Where during the Course of the Proceeding, a change has taken place in the constitution of Tribunal by reason of any vacancy having been filled or by any reason, it shall not be necessary to commence the proceeding afresh and the proceedings may be continued from the stage, at which the change took place and it shall be lawful for the Tribunal to act on evidence, affidavits and other materials already placed before it, prior to change in constitution as aforesaid.

35. *Striking out pleadings*—The tribunal may at any stage of the proceedings order to struck out or amend any matter in any pleadings.

(a) Which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious, or

(b) Which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the reference, or

(c) Which is otherwise an abuse of the process of the Tribunal.

36. *Rejection of petition*—The petition shall be rejected in the following cases :-

(a) Where it does not disclose a cause of action;

- (b) Where the relief claimed is undervalued, and the petitioner, on being required by the Tribunal to correct the valuation within a time to be fixed by the Tribunal fails, to do so:
- (c) Where the relief claimed is properly valued, but the reference is insufficiently stamped and the petitioner on being required to pay requisite court fee within a time to be fixed by the Tribunal, fails to do so.
- (d) Where the reference appears from the statement in the petition to be barred by any law.

37. *Procedure on rejecting reference*—Where a petition is rejected the Tribunal shall record an order to that effect with the reasons for such order.

38. *Withdrawal and adjustment of references*—(1) At any time after the institution of a reference, the petitioner may as against all or any of the respondents abandon his reference or abandon a part of his claim.

(2) Where the Tribunal is satisfied :-

- (a) That a reference must fail by reason of some formal defect, or
- (b) That if there are sufficient grounds for allowing the petitioner to institute a fresh reference for the subject matter of such reference or part of a claim, it may, on such terms as it, thinks fit, grant the petitioner permission to withdraw from such reference or such part of the claim with liberty to institute a fresh reference in respect of the subject matter of such reference or such part of the claim.

(3) Where the petitioner :-

- (a) Abandons any reference or part of claim under sub-regulation (1); or
- (b) Withdraws from a reference or part of a claim without the permission referred to in sub regulation (2); he shall be liable for such costs as the Tribunal may award and shall be precluded from instituting any fresh reference in respect of such subject matter or such part of the claim.

39. *Compromise of reference*—Where it is proved to the satisfaction of the Tribunal that a reference has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise (in writing and signed by the parties) or where the respondent satisfies the petitioner in respect of the whole or any part of the subject matter of the reference, the Tribunal shall record such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance with law.

40. *Powers and functions of the Registrar*—(1) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall perform such other functions as are assigned to him under these regulations or as may be assigned by the Chairman by separate order.

(2) The Registrar may, with the approval of the Chairman designate to the Joint Registrar/ Deputy Registrar/Section Officer any function or power required to be performed or exercised by the Registrar.

(3) In the absence of the Registrar, the Joint Registrar/ Deputy Registrar/Section Officer may exercise all the powers and perform all the functions of the Registrar.

(4) The official seal shall be kept in the custody of the Registrar.

(5) Subject to any general or special direction by the Chairman, the seal of the Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the Registrar or the Joint Registrar/ Deputy Registrar/Section Officer.

40.(A) *Additional powers and duties of Registrar*—In addition to powers conferred elsewhere in these regulations, the Registrar shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the Chairman namely;

- (i) To decide all questions arising out of the scrutiny of the petitions/applications before they are registered;
- (ii) To require any petition/application presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Act and the rules before the case is fixed for hearing;
- (iii) To grant leave to inspect the records of the disposed of cases of Tribunal;
- (iv) To requisition records from the custody of any court or other authority;
- (v) To receive and dispose of applications by parties for return of documents in disposed of cases.

41. *Constitution of Benches*—The Chairman shall regulate the constitution of Benches for the cases and the matters of the Tribunal by issuing such standing order from time to time in pursuance of section 10(1) of the Act for convenient transaction of the business of Tribunal.

42. *Seal*—The Tribunal shall use a seal of its own.

43. *Working hours*—The office and the court of the Tribunal shall remain open daily, except on authorised holidays, for the transaction of business before them. The office hour shall be as applicable to offices of the State Government.

The hours of the sitting of the Tribunal or Benches shall be between 10.00 am to 5.00 pm. With a recess between 1.30 pm. and 2.15 pm. The timing may however be suitably be changed by the Chairman, as and when necessary.

44. *Procedure in some other matters of the Tribunal*—The Tribunal shall follow the Rules and practice of the Patna High Court in the matter of procedure to obtain information and copies, preservation, Destruction and custody of records, grant of certified copies, maintenance of and procedure relating to accounts, cancellation of court fee labels, registration of legal practitioners clerk and other such matters regarding practice and procedure of the Tribunal not referred to earlier, in the form and manner as applicable to the Tribunal consistent with the Act and the Rules of the Tribunal till separate regulations on such matters are made by the Tribunal.

45. *Cause List*—Cause list shall be published regularly showing the business of Tribunal indicating the stage of the cases, nature of the cases, the case nos, names of parties, Advocates representing the parties and the Benches before whom the cases have been listed for information to all concerned.

JUSTICE SADANAND MUKHARJEE,

Chairman,

Bihar Public Works Contracts

Disputes Arbitration Tribunal

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 625-571+450-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>